हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्ष: 11 अंक: 169 लखनऊ, शुक्रवार 13 फ़रवरी 2026 पृष्ठ: 04 मूल्य: 01 रूपये

ट्रेड यूनियन और किसान संगठनो के भारत बंद को मिला व्यापक समर्थन

30 करोड़ से अधिक श्रमिक आंदोलन से जुड़े

इन सेवाओं पर पड़ा असर

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। 12 फरवरी 2026 को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने भारत–US अंतरिम ट्रेड फ्रेमवर्क और चार नए लेबर कोड के विरोध में देशव्यापी हड़ताल (भारत बंद) का आह्वान किया। संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) समेत कई संगठनों ने इस बंद को समर्थन दिया। आयोजकों ने दावा किया कि करीब 30 करोड़ श्रमिक इस आंदोलन से जुड़े।

भारत बंद क्यों बुलाया गया?

संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने भारत–US अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट का विरोध करते हुए बंद का आह्वान किया। आरोप है कि इस समझौते से भारतीय किसानों को नुकसान हो सकता है। SKM के संयोजक हन्नान मूला ने कहा कि सस्ते अमेरिकी आयात भारतीय कृषि को कमजोर कर सकते हैं। उन्होंने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के इस्तीफे की मांग भी की।

प्रमुख मांगें क्या हैं?

ट्रेड यूनियनों ने चार लेबर कोड को रद्द करने, ड्राफ्ट सीड बिल और बिजली संशोधन विधेयक वापस लेने तथा "SHANTI Act" को निरस्त करने की मांग की है। इसके अलावा मनरेगा की बहाली और 'विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025' को समाप्त करने की भी मांग की गई है।

पीयूष गोयल बोले – किसानों के हित सुरक्षित

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने समझौते का बचाव करते हुए कहा कि किसानों और डेयरी सेक्टर के हितों की रक्षा की गई है तथा कुछ उत्पादों को टैरिफ रियायतों से बाहर रखा गया है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने चार नए लेबर कोड का विरोध किया। यूनियनों का आरोप है कि ये कोड श्रमिकों की सुरक्षा और नौकरी की स्थिरता को कमजोर करते हैं।

किन सेवाओं पर पड़ा असर?

आयोजकों के अनुसार 30 करोड़ से अधिक श्रमिकों की भागीदारी का दावा किया गया। बंद का समर्थन करने वाले प्रमुख संगठनों में CITU, AITUC, HMS, INTUC, AIUTUC, SEWA, AICCTU, LPF और UTUC शामिल हैं। कई इलाकों में राष्ट्रीयकृत बैंकों, बीमा कंपनियों, डाकघरों और खनन गतिविधियों पर असर देखा गया। अस्पताल, मेडिकल सेवाएं, एयरपोर्ट, निजी कार्यालय और एटीएम जैसी आवश्यक सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होने की उम्मीद जताई गई।

छत्तीसगढ़ में मिलाजुला असर

रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में राष्ट्रीयकृत बैंक बंद रहे। बीमा, डाक विभाग और खनन गतिविधियां आंशिक रूप से प्रभावित हुईं। हालांकि परिवहन सेवाएं सामान्य रहीं और दुर्ग जिले सहित कई क्षेत्रों में जनजीवन पर सीमित प्रभाव पड़ा। भिलाई स्टील प्लांट में कामकाज सामान्य रहा। राज्य में किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।

गुजरात में सामान्य जनजीवन

गुजरात में भारत बंद का असर सीमित रहा। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में बाजार, औद्योगिक इकाइयां, स्कूल–कॉलेज और परिवहन सेवाएं सामान्य रहीं। हीरा और टेक्सटाइल उद्योग में कामकाज जारी रहा। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल में हिस्सा लिया, लेकिन बैंकिंग संचालन पर बड़ा असर नहीं पड़ा।

मध्य प्रदेश में आंशिक प्रदर्शन

मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में प्रदर्शन हुए। 25,000 से अधिक रक्षा प्रतिष्ठानों के असैन्य कर्मचारियों ने एक घंटे देरी से ड्यूटी जॉइन कर विरोध दर्ज कराया। बाजार और शैक्षणिक संस्थान खुले रहे। भोपाल और जबलपुर में ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं ने रैलियां और नारेबाजी की।

सेब उत्पादक किसानों की चिंता

हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक किसानों ने आयात शुल्क में संभावित बदलाव को लेकर चिंता जताई और विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की तैयारी की। उनका कहना है कि सस्ते आयात से स्थानीय बागानों पर असर पड़ सकता है।

विपक्ष का विरोध और राजनीतिक समर्थन

कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने हड़ताल का समर्थन किया। CPI सांसद पी. सांडोश कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी श्रमिकों के साथ खड़ी है और लेबर कोड वापस लेने की मांग का समर्थन करती है। संसद के बजट सत्र के दौरान भारत–US अंतरिम व्यापार समझौता और श्रम सुधारों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव जारी है।

भारत की सबसे बड़ी रक्षा डील को डीएसी की मंजूरी, खरीदे जाएंगे 114 राफेल जेट और 6 पी–8आई एयरक्राफ्ट

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने अपनी बैठक में 114 राफेल लड़ाकू विमानों और 6 पी–8आई एयरक्राफ्ट, समुद्री निगरानी विमान की खरीद को मंजूरी दे दी है। यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी रक्षा खरीद योजनाओं में से एक मानी जा रही है। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य चुनौतियों को देखते हुए भारतीय वायुसेना को आधुनिक, भरोसेमंद और तेज प्रतिक्रिया देने वाले लड़ाकू विमानों की जरूरत है। राफेल, 4.5.जनरेशन का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है। डीएसी की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास अंतिम स्वीकृति के लिए जाएगा। 114 राफेल से भारतीय वायुसेना को 6–7 नए स्क्वाड्रन मिलेंगे। वायुसेना के पास वर्तमान में लगभग 30 स्क्वाड्रन हैं, जबकि जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है। डीएसी की मंजूरी के बाद भारतीय नौसेना को 6 नए पी–8आई विमान भी मिलेंगे। यह विमान समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों की निगरानी, लंबी दूरी की समुद्री गश्त और मल्टी.मिशन ऑपरेशन जैसे कार्यों में बेहद प्रभावी माने जाते हैं। भारतीय नौसेना पहले से ही 12 पी–8आई ऑपरेट कर रही है, जिनके 40,000 से अधिका दुर्घटना.मुक्त उड़ान घंटे इन्हें और विश्वसनीय बनाते हैं। 114 राफेल

और 6 पी–8आई की डीएसी मंजूरी वर्तमान भू–राजनीतिक माहौल में बेहद अहम है। विशेषकर जब चीन डीएसी पर अपनी तैनाती बढ़ा रहा है, पाकिस्तान लगातार सैन्य गतिविधियां तेज कर रहा है। ऐसे में वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या ऐतिहासिक रूप से कम है। इन तकनीकों के कारण राफेल हवा से हवा और हवा से जमीन– दोनों तरह के मिशन बेहद प्रभावी तरीके से अंजाम दे सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी राफेल के जरिए ही भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। जिससे यह विमान वायुसेना के लिए पहले से ट्रायल. एंड.टेस्टेड साबित हो चुका है। इसी वजह से वायुसेना राफेल को प्राथमिकता पर खरीदना चाहती है।

धर्मेंद्र प्रधान ने किया आईआईएम लखनऊ में एआई कार्यक्रमों का शुभारंभ

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 के दौरान आई आईएम लखनऊ में एआई आधारित नए शैक्षणिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत नैतिक और जिम्मेदार एआई के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि एआई को प्रबंधन शिक्षा, नवाचार और समाजोपयोगी कार्यों से जोड़ना समय की आवश्यकता है। भारत की विशाल युवा शक्ति स्वदेशी एआई मॉडल

विकसित कर वैश्विक स्तर पर योगदान दे सकती है। आईआईएम लखनऊ के निदेशक प्रो. एम. पी. गुप्ता ने बताया कि ये कार्यक्रम प्रबंधन विशेषज्ञता और तकनीकी दक्षता का समन्वय प्रस्तुत करेंगे। इनका उद्देश्य तकनीकी नवाचार को व्यावसायिक रूप से उपयोगी बनाना और विकसित भारत/2047 के लक्ष्य को गति देना है। उन्होंने बताया कि संस्थान तीन प्रमुख पाठ्यक्रम शुरू करेगा, जिनमे चार वर्षीय बीएस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स, दो वर्षीय टेक एमबीए, तथा पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएस टेक एमबीए शामिल है। वहीं बीएस कार्यक्रम 2026–27 सत्र से प्रारंभ होगा, जबकि टेक एमबीए 2027–28 से शुरू किया जाएगा। आईआईएम लखनऊ का यह कदम डिजिटल इंडिया और इंडिया एआई मिशन जैसी राष्ट्रीय पहलों को मजबूती देगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को डिजिटल नेतृत्व, उद्यमिता और एआई आधारित निर्णय क्षमता से लैस किया जाएगा, जिससे भारत वैश्विक एआई परिदृश्य में सशक्त भूमिका निभा सके।

संक्षिप्त समाचार

अडानी पावर ने परमाणु ऊर्जा कारोबार के लिए अडानी एटॉमिक एनर्जी का किया गठन

एजेंसी

नयी दिल्ली। अडानी पावर ने परमाणु एवं नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त बिजली के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड (एएईएल) का गठन किया है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि एएईएल को 5,00,000 रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ गठित किया गया है। इसे 10 रुपए अंकित मूल्य वाले 50,000 शेयर में विभाजित किया गया है।

एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई : 100 करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, दो सदस्य गिरफ्तार

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। एसटीएफ उत्तर प्रदेश ने अंतरराज्यीय संगठित गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर 100 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी चोरी का खुलासा किया है। आरोपित फर्जी फर्म बनाकर कूट रचित इनवॉइस और ई–वे बिल के जरिए वास्तविक फर्मों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) बेचते थे, जिससे राजस्व को भारी क्षति पहुंची। गिरफ्तार आरोपितों में संदीप कुमार (33) निवासी उत्तर दिल्ली और अमन उपाध्याय (21) शामिल हैं। दोनों को 12 फरवरी 2026 को शाम 4:30 बजे एसटीएफ फील्ड इकाई नोएडा कार्यालय में

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किया गया।

इनके पास से दो लैपटॉप, तीन मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, आधार व पैन कार्ड, दो मोहरें और 4650 रुपये नकद बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बोगस फर्म पंजीकृत कराते थे। बिना वास्तविक लेन–देन के फर्जी सेल इनवॉइस और ई–वे बिल बनाकर जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करते और फर्जी रिटर्न दाखिल करते थे। बैंक खातों के माध्यम से लेन–देन दिखाकर बाद में रकम नकद या अन्य फर्जी फर्मों के जरिए वापस कर दी जाती थी। एसटीएफ के अनुसार, दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में कई बोगस फर्मों के माध्यम से सर्कुलर ट्रेडिंग कर करोड़ों रुपये की जीएसटी चोरी की गई। मामले में पूर्व में दर्ज मुकदमे में बीएनएस, आईटी एक्ट और जीएसटी एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई हैं। गिरफ्तार आरोपितों को संबंधित न्यायालय में पेश किया जाएगा, जबकि अन्य फरार आरोपितों की तलाश जारी है।

मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी ढेर, दो पुलिसकर्मी घायल

बीएनई

मुजफ्फरनगर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के विज्ञानी रोड पर बुधवार देर रात पुलिस ने एक सशस्त्र मुठभेड़ में 50 हजार रुपये का इनामी बदमाश अमजद को मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान दो पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारे गये बदमाश पर लूट, हत्या, डकैती समेत करीब 40 जघन्य मुकदमे दर्ज थे और वह अंतरराज्यीय गिरोह का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्रामीण इलाके के जंगल के समीप कुछ बदमाश हैं, जो लूट सहित कई मामलों में वांछित चल रहे हैं। सूचना के आधार पर थाना बुढाना, थाना तितावी एवं थाना शाहपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी कर सघन चेकिंग शुरू की। इस दौरान पुलिस ने बाइक सवार संदिग्ध बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन खुद को घिरा देख, उन्होंने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान आत्मरक्षार्थ फायरिंग में बदमाशों की गोलियां एसपी देहात आदित्य बंसल की गाड़ी पर लगीं।

वहीं कई गोलियां पुलिसकर्मियों की बुलेटप्रूफ जैकेट पर भी लगीं। इस दौरान दारोगा संदीप और सिपाही अशफाक घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अमजद को कई गोलियां लगीं जिससे वह घायल हो गया। घायल अमजद को पुलिस टीम द्वारा तत्काल सीएचसी बुढाना में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस बीच उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल से एक बाइक, एक कारबाइन और एक पिस्टल बरामद की है। पुलिस के मुताबिक अमजद अन्तर्राज्यीय स्तर का शातिर अपराधी था, जिसके विरुद्ध हत्या, लूट, चोरी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट एवं एनडीपीएस एक्ट सहित लगभग 40 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। वह थाना बुढाना पर पंजीकृत मुअसं. 459/2025 धारा 309(4) बीएनएस तथा मु0अ0सं0 10/2026 धारा 309(4), 351(3) बीएनएस में वांछित चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर सहारनपुर परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा 50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

केंद्रीय बजट 2026-27 में एमएसएमई, स्किलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर, पीएम मोदी ने बताया गेमचेंजर

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026–27 की सराहना करते हुए इसे भारत के आर्थिक परिवर्तन का ब्लूप्रिंट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट सुधारों, छोटे उद्योगों, कौशल विकास, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान देता है और देश को नई विकास दिशा प्रदान करेगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, लोकसभा में अपने भाषण में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस बात का विस्तृत विवरण दिया कि इस वर्ष का बजट हमारे राष्ट्र के आर्थिक परिवर्तन में कैसे योगदान देगा। उन्होंने रिफॉर्म एक्सप्रेस, लघु एवं मध्यम उद्यमों को समर्थन, कौशल विकास, अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों और अन्य बातों पर जोर दिया। बीते 1 फरवरी को संसद में पेश किए गए इस बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) पर विशेष फोकस रखा गया है, जो देश की जीडीपी में लगभग 30 प्रतिशत योगदान देता है और 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। वित्त मंत्री ने एमएसएमई के लिए कर्ज की उपलब्धता बढ़ाने, नियमों को सरल बनाने और लक्षित प्रोत्साहन देने की घोषणा की है, ताकि छोटे उद्योग वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं से जुड़ सकें और विस्तार कर सकें। उन्होंने कहा कि एमएसएमई भारत की विकास यात्रा की रीढ़ हैं और यह बजट उन्हें नवाचार और रोजगार सृजन के लिए आवश्यक सहयोग देगा। कौशल

विकास और रोजगार सृजन भी बजट की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल हैं। सरकार ने ग्रीन एनर्जी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल तकनीक जैसे उभरते क्षेत्रों के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित करने की नई पहल का प्रस्ताव रखा है। उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच साझेदारी को भी बढ़ावा देने की योजना है, ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी सरकार ने अगली पीढ़ी की परियोजनाओं पर जोर दिया है। डिजिटल कनेक्टिविटी, नवीकरणीय ऊर्जा कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और शहरी विकास में निवेश बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, स्वास्थ्य और शिक्षा को भी बजट में प्राथमिकता दी गई है। इन क्षेत्रों में बजट बढ़ाने और सुधारों के जरिए दूरदराज व पिछड़े इलाकों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट ऐसे समय में आया है जब वैश्विक अनिश्चितताओं और बदलती सप्लाई चेन के बीच भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सरकार ने विकासोन्मुख खर्च के साथ–साथ वित्तीय अनुशासन पर भी जोर देने की बात दोहराई है।

घुसखोर पंडत पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा, किसी वर्ग को इस तरह के शीर्षक से अपमानित नहीं किया जा सकता

एजेंसी

नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने श्घुसखोर पंडतश शीर्षक पर अप्रसन्नता जताते हुए फिल्म निर्माता नीरज पांडे से बृहस्पतिवार को कहा कि आप इस तरह के शीर्षक का उपयोग करके समाज के किसी वर्ग का अपमान नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय ने ओटीटी मंच नेटफ्लिक्स पर मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म की रिलीज पर रोक लगाए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने फिल्म के खिलाफ दायर याचिका पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और पांडे को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा, इस तरह के शीर्षक का इस्तेमाल करके आप समाज के एक वर्ग को अपमानित क्यों कर रहे हैं? यह नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध है।

लेम्बोर्गिनी कार हादसे में कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा को बड़ी राहत, कोर्ट ने आरोपी को दी जमानत

बीएनई

कानपुर। चर्चित लेम्बोर्गिनी हादसे मामले में आरोपी शिवम मिश्रा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने शिवम मिश्रा की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उसे जमानत दे दी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की दलीलों और केस डायरी के अवलोकन के बाद न्यायालय ने जमानत मंजूर की। हालांकि, अदालत ने जमानत के साथ आवश्यक शर्तें भी लगाई हैं। आप को बता दें कि 8 फरवरी की रात कानपुर का पॉश इलाका ग्वालटोली उस वक्त दहल गया, जब तंबाकू किंग केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा की तेज रफ्तार लैंबॉर्गिनी ने 6 लोगों को रौंद दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक मोटरसाइकिल सवार हवा में 10 फुट ऊपर उछल गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिवम मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस हाई–प्रोफाइल मामले में आज उस वक्त नया मोड़ आया जब शिवम का ड्राइवर मोहन कोर्ट पहुंचा। मोहन ने दावा किया कि गाड़ी वह चला रहा था और तकनीकी खराबी के कारण हादसा हुआ। हालांकि, कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए ड्राइवर का सरेन्डर स्वीकार नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुलिस रिकॉर्ड में मोहन का नाम वॉन्टेड की लिस्ट में नहीं है, इसलिए उसका आत्मसमर्पण स्वीकार नहीं किया जा सकता। शिवम के पिता और वकील दावा कर रहे हैं कि शिवम को मिर्गी के दौरे आते हैं और वह गाड़ी नहीं

चला रहा था। लेकिन घटना के तुरंत बाद का एक वीडियो अब प्राइम एविडेंस बन चुका है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ड्राइविंग सीट पर शिवम मिश्रा ही बैठा है। एक बाउंसर, जिसके हाथ में वॉकी–टॉकी है, शिवम को सीट से बाहर निकलने में मदद कर रहा है।

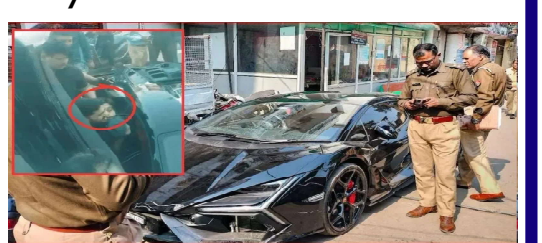

संपादकीय

विपक्ष को मिली आंशिक सफलता

राहुल गांधी यानी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आखिरकार बुधवार को संसद में भाषण दे पाए। पिछले सोमवार जब उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने की कोशिश की थी, तो लगातार उन्हें दो दिन रोका गया और फिर बिना चर्चा के ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया। गनीमत है कि बजट पर ऐसा नहीं हुआ और राहुल गांधी ने संसद में अपना भाषण दिया। राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा करते हुए केंद्र सरकार पर देश की संप्रभुता और डेटा को अमेरिका के हाथों गिरवी रखने का गंभीर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने मार्शल आर्ट्स के श्ग्रिपश और श्चोकश तकनीक का उदाहरण देते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहरी ताकतों के दबाव में श्सरेंडरश कर चुके हैं। अपने भाषण की शुरुआत में राहुल ने बताया कि मार्शल आर्ट्स में लक्ष्य होता है प्रतिद्वंद्वी पर पकड़ बनाना। एक बार पकड़ आ गई, तो गला चोक किया जाता है और विपक्षी 2–3 बार थपथपा करके समर्पण कर देता है। यही आज भारत की राजनीति में हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मार्शल आर्ट्स में तो ग्रिप, चोक और सरेंडर सब नजर आते हैं, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता। इसके बाद राहुल गांधी ने आर्थिक सर्वे पर अपनी बात रखी और कहा कि मैं आर्थिक सर्वेक्षण देख रहा था। मुझे दो मुख्य बिंदु मिले। पहला, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां भू–राजनीतिक संघर्ष तीव्र होता जा रहा है। चीन, रूस और अन्य शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती दे रही हैं। दूसरा, हम ऊर्जा और वित्तीय हथियारों के युग में जी रहे हैं। इसका मुख्य अर्थ यह है कि हम स्थिरता के युग से अस्थिरता के युग की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है, और हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनएसए) ने भी यही कहा है, कि युद्ध का युग समाप्त हो गया है। वास्तव में, हम युद्ध के युग में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए हम अस्थिरता के युग में प्रवेश कर रहे हैं। डॉलर को चुनौती मिल रही है, और अमेरिकी वर्चस्व को भी चुनौती मिल रही है। हम एक महाशक्ति के युग से एक ऐसे नए युग की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। यह एक अस्थिर दुनिया है, और आर्थिक सर्वेक्षण भी यही कहता है, और मैं इससे सहमत हूं। राहुल गांधी ने ईरान, यूक्रेन जैसे वैश्विक युद्धों का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया एक खतरनाक दौर में है। राहुल ने दावा किया कि अमेरिका और चीन के बीच की लड़ाई में सबसे कीमती चीज श्इंडियन डेटाश है। यानी आम भारतीयों की निजी जानकारी जिस तरह डेटा में तब्दील होकर वैश्विक शक्तियों के पास पहुंच रही हैं, उस पर राहुल ने चिंता जताई। साथ ही अमेरिका से डील को उन्होंने बराबरी का सौदा नहीं माना और दावा किया कि इंडिया गठबंधन होता तो ट्रंप से बराबरी पर बात करता, लेकिन मौजूदा सरकार ने श्नौकरश की तरह डेटा सौंप दिया है। वहीं किसानों के हक की आवाज उठाते हुए राहुल ने कहा कि मोदीजी ने अमेरिका के लिए दरवाजे खोलकर भारतीय किसानों को कुचलने की तैयारी की है। हमारे किसानों पर इतना बड़ा हमला कभी नहीं हुआ। वहीं बांग्लादेश पर अमेरिका ने शून्य टैरिफ लगाया है, जिससे भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ेगा, इस पर राहुल ने मोदी सरकार को घेरा। राहुल जब बिंदुवार तरीके से मोदी सरकार को बजट और अमेरिका से सौदे पर घेर रहे थे, तब सदन में बैठे सत्तापक्ष के लोग काफी बेचौन दिख रहे थे। इसके बाद राहुल गांधी ने जैसे ही अनिल अंबानी, हरदीप पुरी और एपस्टीन फाइल्स का जिक्र किया। उन्हें फौरन नियम याद दिलाए जाने लगे। जगदंबिका पाल ने उन्हें बजट पर बोलने को कहा, और कहा कि जो सदन का सदस्य नहीं है, अपना पक्ष रखने के लिए यहां नहीं है, उस पर आप आरोप नहीं लगा सकते। इस पर के सी वेणुगोपाल ने पूछा कि क्या नियम केवल हमारे लिए हैं, क्योंकि इसी सदन में कुछ दिन पहले दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्रियों पर भी बेतुके आरोप लगाकर कीचड़ उछाला गया था। बहरहाल, बार–बार की टोका–टाकी के बाद भी राहुल रुके नहीं और उन्होंने सनसनीखेज दावा किया कि अनिल अंबानी का नाम श्एपस्टीन फाइल्सश में है, इसलिए वे जेल में नहीं हैं। उन्होंने हरदीप पुरी का नाम भी इस विवाद से जोड़ा और कहा कि वे तो संसद के सदस्य हैं। अपने भाषण में राहुल ने पूछा कि क्या आपको देश को बेचने में, हमारी मां, भारत माता को बेचने में शर्म नहीं आई। राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी का नाम भी लिया कि अमेरिका में उनके खिलाफ मामला है, इसका भी संबंध इस ट्रेड डील से है। हालांकि अडानी का नाम आते ही फिर से राहुल को टोकने और बोलने से रोकने का सिलसिला शुरु हो गया। इस तरह राहुल गांधी ने एक बार फिर विपक्ष की ताकत और सच की ताकत का एहसास भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को करा दिया। हालांकि जगदंबिका पाल ने उन्हें दो–तीन बार राहुल–राहुल कह कर टोका तो कांग्रेस ने इस पर भी आपत्ति जताई है कि आप भाजपा के सदस्यों के लिए जी और राहुल गांधी के लिए केवल राहुल कैसे कह रहे हैं। लेकिन इस तरह का पक्षपात अब बार–बार जनता देख ही रही है। आज राहुल गांधी ने जितनी बार प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया, भाजपा सांसद परेशान दिखे।

राशिफल

मेष :– आज आप सांसारिक बातें भूलकर आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में संलग्न रहेंगे। गहरी चिंतनशक्ति आपके मानसिक भार को हल्का करेगी। बोलने पर संयम रखने से अनर्थ से बच जाएंगे।

वृषभ :– आप जीवनसाथी की निकटता का सुख प्राप्त कर सकेंगे। परिवार के साथ सामाजिक समारोह में बाहर घूमने या पर्यटन पर जाएंगे और आनंद में समय व्यतीत होगा।

मिथुन :– अधूरे कार्यों की पूर्णता के लिए आज का दिन शुभ है। परिवार में आनंद और उल्लास रहेगा। स्वास्थ्य बना रहेगा। कार्यों में यश और कीर्ति मिलेगी। नौकरीपेशा वालों को लाभ होगा।

कर्क :– अच्छे मन से दिन व्यतीत करने की गणेशजी सलाह देते हैं, क्योंकि आज का दिन शारीरिक और मानसिक रूप से उद्वेगपूर्ण रहेगा। पेट दर्द परेशान करेगा। धन खर्च की संभावना है।

सिंह :– आज मानसिक अस्वस्थता रहेगी। परिजनों के साथ मनमुटाव की स्थिति आएगी। माताजी की तबीयत खराब हो सकती है। नकारात्मक विचारों से हताशा उत्पन्न होगी।

कन्यारू बिना विचारे साहस करने के प्रति गणेशजी चेतावनी देते हैं। भावनात्मक सम्बंध स्थापित होंगे। मित्रों और स्नेहीजनों के साथ मुलाकात होगी। विरोधियों का डटकर सामना करेंगे।

तुला :– आज की मानसिक वृत्ति नकारात्मक रहेगी। क्रोध आवेश में वाणी पर संयम खोने से पारिवारिक सदस्यों के साथ विवाद होगा। अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे। स्वास्थ्य खराब होगा।

वृश्चिक :– आज का दिन शुभ होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से प्रसन्नता रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ खुशी से समय बीतेगा। धन लाभ का योग है।

धनु :– क्रोध के कारण पारिवारिक सदस्यों के साथ सम्बंध बिगड़ेंगे। आपकी वाणी और व्यवहार झगड़े का कारण बन सकते हैं। दुर्घटना से बचें। बीमारी के पीछे धन खर्च होगा।

मकर :– आज का दिन हर क्षेत्र में लाभदायक है। स्नेहीजनों और मित्रों से मिलना होगा। प्रिय व्यक्तियों के साथ मुलाकात रोमांचक रहेगी। व्यापार–धंधे में आय वृद्धि होगी।

कुंभ :– हर कार्य सरलतापूर्वक हल होंगे और उनमें सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिस्थिति बनेगी। सरकारी कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे। स्वास्थ्य बना रहेगा। धन प्राप्ति का योग है।

मीन :– आज के दिन की शुरुआत भय के साथ होगी। शरीर में सुस्ती और थकान रहेगी। कोई भी कार्य पूरा न होने पर हताशा होगी। भाग्य साथ न देता हुआ प्रतीत होगा। व्यर्थ में पैसे खर्च होंगे।

लोकसभा–अध्यक्ष के विरुध्द अविश्वासः लोकतंत्र की अग्निपरीक्षा

—ललित गर्ग

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी लोकतंत्र के लिये एक चिन्ताजनक घटना है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक प्रणाली नहीं, बल्कि निरंतर संवाद, असहमति के सम्मान और संस्थागत विश्वास पर टिकी हुई एक जीवंत परंपरा है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में संसद इस लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, जहाँ न केवल नीतियाँ बनती हैं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा बोलती है। ऐसे में जब लोकसभा अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की खबरें सामने आती हैं, तो यह घटना किसी एक व्यक्ति या दल तक सीमित न रहकर पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर देती है। विपक्षी दलों द्वारा यह आरोप लगाया जाना कि उन्हें, विशेषकर नेता प्रतिपक्ष को, सदन में बोलने का समुचित अवसर नहीं मिल रहा, और इसी आधार पर अध्यक्ष की निष्पक्षता पर सवाल उठाना, एक गहरी चिंता का विषय है। यह चिंता इसलिए भी अधिक गंभीर हो जाती है क्योंकि अध्यक्ष का पद परंपरागत रूप से सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन का प्रतीक माना जाता रहा है। लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका केवल कार्यवाही संचालित करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह सदन की गरिमा, लोकतांत्रिक मर्यादा और सभी पक्षों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की संवैधानिक जिम्मेदारी भी निभाते हैं। यदि विपक्ष का एक बड़ा वर्ग यह महसूस करने लगे कि अध्यक्ष का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है या उनकी आवाज को व्यवस्थित रूप से दबाया जा रहा है, तो यह केवल राजनीतिक असंतोष नहीं, बल्कि संस्थागत अविश्वास का संकेत होता है। 100 से अधिक सांसदों द्वारा हस्ताक्षर कर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी यह दर्शाती है कि मामला क्षणिक आक्रोश का नहीं, बल्कि लंबे समय से पनप रही असहमति और संवादहीनता का परिणाम है। लोकसभा अध्यक्ष सदन के संरक्षक की भूमिका में होते हैं, जिनके प्रति विश्वास जरूरी होता है और उनसे भी निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है। हालांकि यह भी उतना ही सत्य है कि संख्या बल के आधार पर इस तरह का प्रस्ताव पारित होना कठिन है, लेकिन लोकतंत्र में कई बार प्रतीकात्मक कदम भी गहरे संदेश देते हैं। विपक्षी दलों द्वारा यह स्पष्ट करना कि वे टकराव के साथ–साथ सुलह का विकल्प भी खुला रखे हुए हैं, और इसी क्रम में विभिन्न वरिष्ठ नेताओं का अध्यक्ष से मुलाकात कर संवाद का प्रयास करना, इस बात का संकेत है कि अभी भी समाधान की गुंजाइश समाप्त नहीं हुई है। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर संसद जैसे सर्वोच्च मंच पर संवाद की जगह हंगामा, नारेबाजी और गतिरोध क्यों हावी होता जा रहा है। क्या यह केवल सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच अविश्वास का परिणाम है, या फिर संसदीय परंपराओं के क्षरण का संकेत? विगत वर्षों में बार–बार यह देखने को मिला है कि महत्वपूर्ण विधेयकों और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर गंभीर चर्चा के बजाय सदन की कार्यवाही बाधित होती रही है। इससे न केवल विधायी कामकाज प्रभावित होता है, बल्कि जनता के बीच यह संदेश भी जाता है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि अपने दायित्वों के प्रति गंभीर नहीं हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह असहमति को स्थान देता है। विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं, बल्कि सरकार को जवाबदेह ठहराना और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना भी है। इसके लिए सदन में बोलने का अवसर, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता और आलोचना का सम्मान अनिवार्य है। यदि विपक्ष यह महसूस करता है कि उसके लिए ये रास्ते संकुचित किए जा रहे हैं, तो उसका आक्रोश सड़कों या नारेबाजी के रूप में फूट पड़ता है, जो अंततः संसद की गरिमा को ही नुकसान पहुँचाता है। दूसरी ओर, विपक्ष द्वारा बार–बार सदन की कार्यवाही बाधित करना भी उतना ही गंभीर दोष है, क्योंकि इससे शासन की प्रक्रिया ठप होती है और जनता के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। इस दोतरफा अविश्वास और आक्रामकता के बीच लोकतंत्र का मूल उद्देश्य कहीं खोता हुआ दिखता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यदि संसद बार–बार हंगामे, निलंबन और गतिरोध की खबरों में रहे, तो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की लोकतांत्रिक छवि को प्रभावित करता है। विकास, नीति और जनकल्याण की चर्चा के स्थान पर यदि टकराव और अविश्वास केंद्र में आ जाए, तो यह भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। लोकतंत्र की मजबूती केवल मजबूत सरकार से नहीं, बल्कि मजबूत विपक्ष और निष्पक्ष संस्थानों से भी आती है। लोकसभा अध्यक्ष जैसे पद से अपेक्षा की जाती है कि वह न केवल नियमों का पालन कराए, बल्कि विश्वास का सेतु भी बने। वहीं विपक्ष से भी यह अपेक्षा है कि वह विरोध को रचनात्मक बनाए, न कि अवरोध का माध्यम। आज आवश्यकता इस बात की है कि संसद को फिर से संवाद का मंच बनाया जाए, जहाँ तीखी असहमति भी मर्यादा में व्यक्त हो और सत्ता व विपक्ष दोनों ही लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराएँ। अविश्वास प्रस्ताव जैसे कदम यदि चेतावनी के रूप में लिए जा रहे हैं, तो उन्हें आत्ममंथन का अवसर भी बनना चाहिए। प्रश्न यह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि यह है कि लोकतंत्र की संस्था को कैसे स्वस्थ, विश्वसनीय और प्रभावी बनाया जाए। जनता ने सांसदों को नारे लगाने या कार्यवाही बाधित करने के लिए नहीं, बल्कि देश के भविष्य पर गंभीर विमर्श के लिए चुना है। यदि संसद इस अपेक्षा पर खरी नहीं उतरती, तो लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है। यह भी तथ्य है कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में श्री ओम बिरला का संसदीय संचालन अब तक सामान्यतः अनुशासित, कार्यकुशल और नियमसम्मत माना जाता रहा है। उनके कार्यकाल में लोकसभा की कार्यवाही को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने, विधायी कार्यों को प्राथमिकता देने और विभिन्न दलों को साथ लेकर चलने का प्रयास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अनेक अवसरों पर उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है तथा संसदीय परंपराओं और नियमों के पालन पर बल दिया है। उनकी छवि एक ऐसे अध्यक्ष की रही है जो सदन को सुचारु रूप से चलाने के लिए होशियारी, धैर्य और व्यावहारिक समझ का प्रयोग करते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, संसदीय मर्यादाओं का आग्रह और संवाद के लिए दरवाज़े खुले रखने की प्रवृत्ति को देखते हुए उनके जैसे लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की स्थिति अपने आप में एक त्रासद और चिंताजनक घटना प्रतीत होती है। यह घटना व्यक्ति विशेष से अधिक उस माहौल की ओर संकेत करती है, जहाँ अविश्वास इतना गहरा हो चुका है कि संवाद और विश्वास के पुल कमजोर पड़ते जा रहे हैं। अंततः यह समय आरोप–प्रत्यारोप से आगे बढ़कर जिम्मेदारी स्वीकार करने का है। सत्तापक्ष को यह समझना होगा कि मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। विपक्ष को यह स्वीकार करना होगा कि विरोध की भी एक मर्यादा और रचनात्मकता होती है। और अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पदों को यह स्मरण रखना होगा कि उनकी निष्पक्षता केवल नियमों के पालन से नहीं, बल्कि व्यवहार और अवसर की समानता से भी सिद्ध होती है। यदि संसद को संवाद का मंच बनाए रखने में हम विफल रहते हैं, तो यह केवल एक सत्र या एक सरकार की विफलता नहीं होगी, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी सामूहिक असफलता मानी जाएगी। यही वह बिंदु है जहाँ हर नागरिक, हर जनप्रतिनिधि और हर संस्था को आत्मचिंतन करना होगा, ताकि विकास की राह में विनाश की संभावनाएँ नहीं, बल्कि संवाद, विश्वास और लोकतांत्रिक परिपक्वता का मार्ग प्रशस्त हो सके।

जो उचित है वही करो

नरेन्द्र मोदी सरकार में संसद सत्र के सुचारू रूप से न चलने के लिए विपक्ष को कई तरह से जिम्मेदार ठहराया जाता है। कभी सदन में हंगामा करने, कभी संसदीय परंपराओं का पालन न करने या मुद्दों से भटकाने के आरोप कई बार विपक्षी सांसदों पर लगाए गए और उन्हें निलंबित भी किया गया। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में ही कम से कम सौ सांसदों के निलंबन का रिकार्ड बना है। लेकिन अब केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजीजू ने एक बेहद गंभीर आरोप कांग्रेस सांसदों पर लगाया है। श्री रिजीजू का कहना है कि श्कम से कम 20–25 कांग्रेस सांसद लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में घुस गए और उनके साथ गाली–गलौज की। जी हां, यही शब्द किरण रिजीजू ने इस्तेमाल किए। उनका कहना है कि मैं भी वहीं था और जो गालियां कांग्रेस सांसदों ने दी, वो मैं बता भी नहीं सकता। श्री रिजीजू ने यह भी कहा कि लोकसभा अध्यक्ष इससे बहुत आहत हैं। वे बहुत नरम इंसान हैं, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाती। इसके बाद किरण रिजीजू ने यह भी कहा कि हमारे कोई सांसद ऐसा व्यवहार करते तो हम उन्हें रोकते, लेकिन उस वक्त प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी अंदर मौजूद थे, और वे उन्हें लड़ने के लिए उकसा रहे थे। पाठक जानते हैं कि पिछले बुधवार ओम बिड़ला ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस की महिला सांसद लोकसभा में प्रधानमंत्री के बैठने की जगह को घेरे हुई थीं और वो उन पर हमला करने की तैयारी में थीं, इसलिए प्रधानमंत्री को लोकसभा में आने से मना किया गया। अब ये नया आरोप कांग्रेस सांसदों पर लगा है कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के साथ ही दुर्व्यवहार किया। अगर इन आरोपों में सच्चाई है तो फिर भाजपा सरकार या ओम बिड़ला किस बात का इंतजार कर रहे हैं, अब तक कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। क्या लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में सीसीटीवी नहीं लगा है, जहां सब कुछ देखा जा सके। ओम बिड़ला को कांग्रेस सांसदों ने कथित तौर पर जो गालियां दीं, उस घटना को देश ने अब तक न देखा न सुना है। लेकिन संसद के भीतर जब भाजपा के तत्कालीन सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा के तत्कालीन सांसद दानिश अली को अपशब्द कहे थे, उसे लोकसभा अध्यक्ष समेत पूरे देश ने देखा और सुना था। तब बिड़ला साहब आहत होने से कैसे चूक गए, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। जहां तक सवाल उनके नरम इंसान होने का है, तो वह व्यक्तिगत तौर पर चाहे जैसे हों, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की आसंदी पर केवल निष्पक्ष होने की जरूरत है, जो अक्सर वे नजर नहीं आते हैं। किरण रिजीजू ने लोकसभा अध्यक्ष के बचाव में यह भी कहा कि उन्होंने एक नियम बताया, जिसका पालन नहीं हुआ और फिर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें बोलने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। वह अपनी मर्जी से बोलेंगे, बिना किसी नियम के...जबकि यह आधा सच है। राहुल गांधी ने सदन में कहा था कि आप यह नहीं कह सकते कि आपको बोलने की इजाजत दी जा रही है। विपक्ष का नेता होने के नाते यह मेरा हक है। इसमें राहुल गांधी ने आसंदी की अवहेलना नहीं की थी, केवल निर्वाचित सांसद का अधिकार बताया था। दरअसल पूरी मोदी सरकार इस समय बुरी तरह घिरी हुई है। अमेरिका से व्यापार सौदे का सच और एपस्टीन मामले में नाम उछलने के बाद जनता के सामने अपनी छवि बचाने की कोशिश भाजपा कर रही है और इसके लिए उसे यही तरीका समझ आ रहा है कि किसी भी तरह कांग्रेस की लकीर छोटी की जाए। इसलिए कभी प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश, कभी लोकसभा अध्यक्ष को गालियों के आरोप लगाए जा रहे हैं। इधर मनोज नरवणे की किताब का सच भी सरकार सामने नहीं आने देना चाहती। इसलिए प्रकाशक से कहलवा दिया गया कि किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है। मनोज नरवणे ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। हालांकि श्री नरवणे को कायदे से यह बताना चाहिए कि जो कुछ राहुल गांधी ने उनके हवाले से कहा है, वो सही है या नहीं। अगर राहुल गांधी गलत हैं, तो फिर श्री नरवणे ने अब तक उन पर कुछ क्यों नहीं कहा, ये बड़ा सवाल है। वैसे राहुल गांधी संसद परिसर में फोर स्टार्स इन ए डेस्टिनी किताब ले आए, तो जवाब देने के लिए केन्द्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह नेहरूजी के कुछ पोस्टर्स ले कर आए। लेकिन उसमें भी भाजपा फंस गई। मंगलवार को सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नियम बनाए कि एआई–जनित सामग्री पर स्पष्ट रूप से लेबल (वाटरमार्क) लगाएं। ऐसी सामग्री में पहचान के लिए संकेत जरूर होने चाहिए। सरकार ने कहा कि एक बार एआई लेबल या मेटा डाटा लगाने के बाद उसे हटाया या दबाया नहीं जा सकता। लेकिन सरकार के बनाए नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए गिरिराज सिंह एआई से बनाए गए पोस्टर्स ले आए। संघ और भाजपा ने नेहरूजी में कमियां ढूंढने की कोशिश में हताश होकर उनके चरित्र हनन का ही तरीका अपनाया है। नेहरूजी के कपड़े पेरिस धुलने जाते थे से लेकर उनके कितनी महिलाओं से संबंध थे और लेडी माउंटबेटन से उनका प्रेम प्रसंग था, जैसे ढेरों ऊटपटांग किस्से पहले पोस्टकार्डों पर और फिर सोशल मीडिया पर घूमते हैं। अब गिरिराज सिंह बाकायदा उन झूठों का पोस्टर छपवाकर ले आए। संसद परिसर में उन्होंने कम से कम पांच पोस्टर पत्रकारों को दिखाए। पहला पोस्टर ए आई से बना है, जिसमें नेहरू और लेडी माउंटबेटन को गलबहियां करते दिखाया गया है। इसमें पीछे राष्ट्रपति भवन दिख रहा है। जाहिर है बीच सड़क पर इस तरह की क्लोज फोटो उस समय तो नहीं खींची गई होगी, लेकिन इसे गिरिराज सिंह ने दिखाया है। दूसरे पोस्टर में तीन फोटो हैं, पहली तस्वीर नेहरूजी के साथ उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित की है। यह तस्वीर अमेरिका की है। इसी पोस्टर में दूसरी तस्वीर भी विजयलक्ष्मी पंडित के साथ है, जो रूस में खींची गई है और इस पोस्टर की तीसरी फोटो में नेहरू विजयलक्ष्मी पंडित की बेटी मतलब अपनी भांजी नयनतारा सहगल के साथ लंदन में हैं। अब भाजपा नेता बताएं कि बहन और भांजी के साथ फोटो खिंचवाने में क्या गलत है। तीसरा पोस्टर फिर एआई से बना है और इसमें पहले पोस्टर की ही तस्वीर है। इस पर लिखा है अंग्रेज की बाहों में नेहरू का सरेंडर। चौथा पोस्टर फिर कश्मीर का सरेंडर के साथ लिखा हुआ है। इसमें दिखाई गई महिला के लिए लेडी माउंटबेटन लिखा है, हालांकि वे तत्कालीन ब्रिटिश डिप्टी हाईकमिश्नर की पत्नी श्रीमती सिमॉन हैं। इन तमाम पोस्टर्स में जिस तरह सरेंडर शब्द लिखा गया है, उसमें भी भाजपा घिर गई है, क्योंकि यही शब्द राहुल गांधी नरेन्द्र मोदी के लिए इस्तेमाल करते हैं। भाजपा ने इसे इस्तेमाल कर कहीं न कहीं राहुल गांधी की बात पर मुहर ही लगाई है। बहरहाल, नेहरूजी पर बोला गया झूठ फौरन पकड़ाई में आ गया और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। भाजपा को लगता है कि जनता उसकी कही हर बात पर पहले की तरह यकीन कर लेगी, तो ऐसा अब नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया का जो हथियार उसके पास है, वह कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष के पास भी है। वैसे भी जनता रोजाना के ऐसे छिछले–उथले आरोपों की राजनीति से तंग आ चुकी है। उसे असल प्रश्नों के असल जवाब चाहिए। राहुल गांधी और समूचा विपक्ष इन्हीं सवालों को संसद में उठाने की लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन भाजपा नेहरू जी से आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। निशिकांत दुबे और गिरिराज सिंह जैसे नेता तो इस तरह फिर भी कुछ सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन नरेन्द्र मोदी को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। बेहतर होगा कि मोदीजी अपनी इन छिद्रों वाली ढालों को परे करें और असली हिम्मत का परिचय देकर विपक्ष के उठाए सवालों के जवाब दें। जो उचित समझो वो करो, इस तरह का टालमटोल वाला रवैया देश के प्रधानमंत्री को नहीं अपनाना चाहिए। उचित क्या है, इसे समझाते हुए उन्हें जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। यानी जो उचित है वही करना चाहिए।

'रिजर्व करंसी' का अपना दर्जा छोड़ने को डॉलर तैयार नहीं

—नारायण रामचंद्रन

2026 की शुरुआत के साथ ही 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं। पहली घटना यह थी कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए 'मजबूत युआन' का स्पष्ट आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर, अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गिरते डॉलर को लेकर जताई जा रही चिंताओं को 'नहीं, यह तो बढ़िया है' कह कर खारिज कर दिया। यह सच है कि शी ने यह बात 2024 में एक बंद मंच पर कही थी, लेकिन चीनी अधिकारियों ने इसे इसी साल सार्वजनिक किया। यह भी सच है कि ट्रम्प लगभग 4 दशकों में डॉलर की बात करने वाले पहले अमरीकी राष्ट्रपति हैं।पहले अमरीकी डॉलर के विभिन्न ऐतिहासिक चक्रों पर एक संक्षिप्त नजर डालें। सबसे पहला चक्र 1971 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत स्वर्ण मानक और डॉलर की स्वर्ण में परिवर्तनीयता को निलंबित करने की चौंकाने वाली घोषणा से शुरू होता है। तब से, डॉलर के 7 प्रमुख चक्र रहे हैं। पहला, 1971–1978रू स्वर्ण मानक छोड़ने के बाद अस्थिरता। दूसरा, 1978–1985रू डॉलर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तीसरा चरण, 1985–1992: प्लाजा समझौता और व्यापारिक सांझेदारों के सहयोग से डॉलर के मूल्य में नियोजित अवमूल्यन। चौथा चरण, 1992–2002: मजबूत डॉलर का युग, जिसमें अमरीका एकमात्र वैश्विक महाशक्ति था। पांचवां चरण, 2002–2012' अमरीका द्वारा महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति में ढील देने के कारण डॉलर का मूल्य कम हुआ, जबकि उभरते बाजारों में तेजी आई। छठा चरण, 2012–2022: मजबूती का एक दशक, जो 2022 के आसपास उच्चतम स्तर पर पहुंचा। सातवां चरण, 2022–2026: डॉलर नए शिखर पर पहुंचा लेकिन 2022 के मध्य में गिरावट शुरू हुई जो 2025 में और तेज हो गई। आज, डी.एक्स.वाई. डॉलर सूचकांक (छह मुद्राओं की एक टोकरी के मुकाबले) अपने 2022 के उच्चतम स्तर से लगभग 13 प्रतिशत नीचे है, अपने 2008 के न्यूनतम स्तर से 30 प्रतिशत ऊपर है और पूर्ण अवधि के रुझान के ठीक मध्य में है। साथ ही, सोना, जिसे कभी–कभी 'एंटी–डॉलर' कहा जाता है और चांदी, तांबा और प्लेटिनम जैसी अन्य धातुएं हाल ही में अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं (हालिया बिकवाली के साथ)। इससे कुछ विश्लेषकों ने इसे 'डॉलर का अवमूल्यन' कहना शुरू कर दिया है। मुद्राओं के संदर्भ में, अवमूल्यन एक गंभीर शब्द है। इस शब्द के लागू होने के लिए निम्नलिखित चारों शर्तों का पूरा होना आवश्यक है–एक, मुद्रा आपूर्ति में भारी वृद्धि, जिसे

आमतौर पर एम2 वृद्धि द्वारा मापा जाता हैय दो, बड़ा राजकोषीय और चालू खाता घाटाय तीन, आसान मौद्रिक नियंत्रण परिस्थितियां, जो आमतौर पर मात्रात्मक सहजता की नीति द्वारा चिह्नित होती हैं और चौथी, देश के आर्थिक प्रबंधन में कम विश्वास। इन चार मापदंडों के आधार पर, आज अमरीका की स्थिति कुछ इस प्रकार है। एम2 द्वारा मापी गई वार्षिक मुद्रा आपूर्ति वृद्धि 5 प्रतिशत है, जो काफी सामान्य है। अमरीका का राजकोषीय घाटा काफी अधिक है (2025–26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5.5 प्रतिशत अनुमानित) और इसका राष्ट्रीय ऋण 39 ट्रिलियन डॉलर है। एक असामान्य स्थिति यह है कि इसमें से 9 ट्रिलियन डॉलर का पुर्नवत्तपोषण 2026 में होना है, जिससे बॉन्ड यील्ड पर दबाव बढ़ सकता है। अमरीका सकारात्मक वास्तविक दरों और मात्रात्मक सख्ती के संयोजन के साथ मध्यम रूप से सख्त मौद्रिक स्थितियों में काम कर रहा है। हाल के समय में डॉलर के 'सामान्यीकरण' की प्रक्रिया तेज हुई है और आज अमरीका को मुद्रा अवमूल्यन का खतरा नहीं है। यह मुख्य रूप से अमरीकी अर्थव्यवस्था के प्रति लोगों की भावना पर निर्भर करता है। प्रबंधन ने डॉलर को कमजोर कर दिया है। पिछले करीब एक साल से भारतीय रुपया उन मुद्राओं में से एक रहा है, जिनकी कीमत डॉलर के कमजोर होने के कारण कम हुई है। आम धारणा के विपरीत, 2025 में विनिमय दर में भारी गिरावट के बावजूद, पिछले कुछ वर्षों में रुपए का वाषक अवमूल्यन केवल 3.1 प्रतिशत रहा है। पिछले 25 वर्षों में रुपए के लिए सबसे खराब 3 साल की अवधि 2011–13 थी, जिसमें 'टैपर टैंट्रम' और डॉलर का अपने आधार पर लौटना शामिल था, जिसने डॉलर की मजबूती के दौर का भी संकेत दिया था। आज भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत है और महामारी के बाद से हमने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को बनाए रखा है। अमरीका के मुकाबले सापेक्ष मुद्रास्फीति अब 25 वर्षों में सबसे कम है और इसमें गिरावट का रुझान दिख रहा है। अमरीका के साथ जल्द ही लागू होने वाले नए व्यापार समझौते को देखते हुए, रुपए–डॉलर विनिमय दर के लिए संभावनाएं सकारात्मक दिखती हैं और यह मुद्रास्फीति के अंतर से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक के पास 700 अरब डॉलर से अधिक का अब तक का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है, जो रुपए में किसी भी अप्रत्याशित गिरावट को रोकने में सक्षम है। अमरीका की मिश्रित औसत टैरिफ दर में एकल–अंकीय से दोहरे–अंकीय स्तर तक की वृद्धि डॉलर पर ऊपर की ओर (नीचे की ओर नहीं) दबाव डालती है। आगामी समय में ट्रेजरी के पर्याप्त पुनर्वित्तपोषण को लेकर चिंताएं 2026 में डॉलर को कमजोर कर सकती हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक डॉलर से हटकर विविधीकरण कर सकते हैं, जिससे डॉलर का प्रभुत्व कुछ हद तक कम हो सकता है लेकिन विश्व की आरक्षित मुद्रा (रिजर्व करंसी) के रूप में इसका स्थान खोना अभी बहुत दूर की बात है। डॉलर के बाहर किए जाने वाले द्विपक्षीय व्यापार का हिस्सा एक छोटे प्रतिशत से बढ़कर एक उच्च आंकड़े तक पहुंच सकता है। भले ही ट्रम्पवाद के कई सामाजिक पहलू उनके राष्ट्रपति पद के दौरान बने रहें लेकिन डॉलर की आरक्षित मुद्रा स्थिति को 'असाधारण विशेषाधिकार' की बजाय बोझ के रूप में देखने का नजरिया शायद ही कायम रहेगा। चीन अपने रेनमिनबी को आरक्षित मुद्रा के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसके लिए आवश्यक संस्थागत विश्वसनीयता में कम से कम एक दशक लगेगा। इससे पहले के लगभग 5 राष्ट्रपति कार्यकालों की तरह, अमरीका जल्द ही 'मजबूत डॉलर' की उस नीति पर लौट आएगा, जो पिछले 40 वर्षों से देश की पहचान रही है। अवमूल्यित डॉलर से अमरीका को फिर से महान नहीं बनाया जा सकता।

"गरिमापूर्ण वृद्धावस्था : वृद्धावस्था देखभाल हेतु मार्गदर्शन" विषय पर शैक्षणिक कार्यक्रम

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। एसजीपीजीआईएमएस के जनरल अस्पताल और अस्पताल प्रशासन विभाग द्वारा जेरियाट्रिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया (यूपी चौप्टर) के तत्वावधान में 11 फरवरी 2026 को हरगोविंद खुराना सभागार में "गरिमापूर्ण वृद्धावस्था : वृद्धावस्था देखभाल हेतु मार्गदर्शन" शीर्षक से एक शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वृद्धावस्था में बुजुर्गों की देखभाल के तौर तरीकों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चिकित्सक और प्रशासक एक मंच पर उपस्थित हुए। यह कार्यक्रम जनरल अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सक एवं नोडल अधिकारी डॉ. प्रेरणा कपूर और संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक एवं प्रोफेसर, अस्पताल प्रशासन आर. हर्षवर्धन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। संस्थान के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर आर. के. धीमन, मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित थे और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रगतिशील पहलों को बढ़ावा देने में उनके निरंतर नेतृत्व की सराहना की गई। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉ. ए. के. सिंह ने बुजुर्गों में गिरने से बचाव पर अपना संबोधन दिया और रुग्णता को कम करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में इसके महत्व पर प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथियों में डीन प्रो. शालीन कुमार और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रो. देवेंद्र गुप्ता

शामिल थे, जिन्होंने वृद्धजनों के अनुकूल स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को विकसित करने के प्रति संस्थागत प्रतिबद्धता पर बल दिया। केजीएमयू, लखनऊ के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर और लखनऊ में जराचिकित्सा (ळमतपंजतपबे) के क्षेत्र में अग्रणी डॉ. कौसर उस्मान ने विकसित हो रही इस विशेषज्ञता पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण साझा किए। तत्पश्चात एसजीपीजीआई के सलाहकार मनोचिकित्सक डॉ. रोमिल सैनी द्वारा एक पैनल चर्चा का संचालन किया गया, जिसमें जनसंपर्क, पोषण, ऑर्थोपेडिक्स और क्रिटिकल केयर मेडिसिन के विशेषज्ञों ने भाग लिया, जो जराचिकित्सा प्रबंधन की बहुविषयक प्रकृति को दर्शाता है। वक्ताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वृद्धावस्था में बुजुर्गों का संज्ञानात्मक आकलन, टीकाकरण और सहायक साधन महत्वपूर्ण हैं, तथापि उनकी गुणवत्तापूर्ण देखभाल के लिए बहुत अनिवार्य है कि उपचार के दौरान उनके सम्मान व गरिमा को बनाये रखते हुये करुणा व संवेदनशीलता के साथ उनकी सेवा सुश्रूसा की जाये। कार्यक्रम के द्वारा करुणापूर्ण देखभाल, सशक्त जीवनष विषय को सुदृढ़ किया गया। संस्थान को वृद्धजनों के अनुकूल बनाने और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मानवीय और संवेदनशील देखभाल को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। उपस्थित सभी लोगों को सहानुभूति, करुणा और मानवता के साथ वृद्ध– देखभाल में भाग लेने की शपथ दिलाई गई।

यूएफबीयू बैंक हड़ताल में शामिल नहीं

तीन बैंक संगठनों की हड़ताल का बैंकों में आंशिक असर

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। केंद्रीय ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में कम्युनिस्ट समर्थित तीन बैंक संगठनों एआईबीईए, एआईबीओए तथा बेफी ने एक दिवसीय हड़ताल रखी. बैंक कर्मियों के संगठन यूएफबीयू के जिला संयोजक अनिल श्रीवास्तव तथा मीडिया प्रभारी अनिल तिवारी ने बताया कि आज की हड़ताल का भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक आदि बैंकों पर कोई असर नहीं हुआ। यह पूरी तरह खुले रहे. हड़ताल का असर उन बैंकों में, जहां इन संगठनों की मेंबरशिप अधिक है, जैसे इंडियन बैंक, केनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक आदि में ज्यादा पड़ा। ज्ञातव्य है कि यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस के सभी 9 संगठनों ने 27 जनवरी को 5 दिवसीय बैंकिंग के समर्थन में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी. आज की हड़ताल पूर्णतः राजनैतिक है जिसका बैंक कर्मचारियों के औद्योगिक या सेवा संबंधी मुद्दों से कोई प्रत्यक्ष सरोकार नहीं है. उन्होंने आगे बताया इन तीनों संगठनों की वैचारिक एवं संगठनात्मक बाध्यता के चलते राजनीतिक हड़तालों में भी उनके सदस्यों को शामिल किया जाता है।

फोरम के जिला संयोजक अनिल श्रीवास्तव (दाएं) तथा मीडिया प्रभारी अनिल तिवारी (बायें)

संक्षिप्त

ग्राहकों ने बंद कराई बीओबी की ब्रांच, शटर गिराकर बाहर बैठे

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी में शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय परिसर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच का शटर ग्राहकों ने गिरा दिया। गुरुवार सुबह 25 से अधिक खाताधारक बैंक पहुंचे और अपनी जमा राशि वापस न मिलने पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने उनको समझाया लेकिन वे शटर बाहर से बंद कर वहीं पर बैठ गए। 3 घंटे से ज्यादा समय तक बैंक का काम बंद है। ज्यादातर ग्राहक बाहर बैठकर नारेबाजी की। दरअसल, इस ब्रांच में शिवा राव नाम के बैंक मित्र ने लोगों की एफडी कराकर उसे खाते में चढ़ाया ही नहीं था। जब एफडी मैच्योर की डेट आई तो लोग बैंक पहुंचे। वहां पहुंचने पर पता चला कि उनकी कोई एफडी हुई ही नहीं थी। कई ग्राहकों के खाते से भी रकम गायब थी। सालिकराम पाल ने बताया कि उनकी बेटी कमला का तिलक कार्यक्रम कल होना है, लेकिन बैंक में जमा किए गए 17 लाख 30 हजार रुपए अब तक वापस नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि परिवार बेहद परेशान है और शादी की तैयारियां अधर में लटक गई हैं। सालिकराम के अनुसार, जब भी वे लोग बैंक के रीजनल ऑफिस जाते हैं तो वहां कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उनसे मिलने या बात करने को तैयार नहीं होता पीड़ित परिवार का कहना है कि शादी जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम से ठीक पहले उनकी जमा पूंजी फंस जाना बेहद दुखद और चिंताजनक है। परिवार ने प्रशासन और बैंक उच्चाधिकारियों से जल्द हस्तक्षेप कर धनराशि वापस दिलाने की मांग की है, ताकि तय समय पर तिलक कार्यक्रम संपन्न हो सके। खाताधारकों का कहना है कि उनकी जीवन भर की बचत दांव पर लगी है, ऐसे में जब तक रकम वापस नहीं मिलती और दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सूचना पर पहुंची पारा पुलिस ने मौके पर स्थिति संभालने का प्रयास किया और प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन खाताधारक अपनी मांगों पर डटे रहे। एहतियात के तौर पर परिसर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बैंक प्रबंधन की ओर से दोपहर तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। फिलहाल परिसर में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और खाताधारकों का धरना लगातार जारी है।

राष्ट्रव्यापी सफल हड़ताल के लिए एआईपीएफ ने दी बधाई

कॉर्पोरेट–हिंदुत्व–राज्य गठजोड़ मिलकर कर रहा लोकतंत्र पर हमला लेबर कोड आधुनिक गुलामी के दस्तावेज

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। मजदूर विरोधी चार लेबर कोड की वापसी, बिजली समेत जन हितैषी सार्वजनिक उद्योग के निजीकरण पर रोक, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून, रोजगार का मौलिक अधिकार और भारत–अमेरिकी व्यापार समझौते को संसद के पटल पर रखने जैसे सवालों पर मजदूर संगठनों और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय हड़ताल की सफलता पर ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट की राष्ट्रीय कार्य समिति ने बधाई दी है। पूरे देश में मजदूरों, किसानों नागरिकों के साथ एआईपीएफ कार्यकर्ता इस हड़ताल में शामिल रहे। लखनऊ में डीएलसी ऑफिस पर हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया गया। प्रेस को जारी बयान में ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट की राष्ट्रीय कार्य समिति ने कहा कि आज देशी–विदेशी कॉरपोरेट, हिंदुत्व और राज्य के गठजोड़ ने लोकतंत्र और आर्थिक संप्रभुता पर हमला बोल दिया है। भारतीय हितों को अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में मोदी सरकार ने गिरवी रख दिया। देश के प्रमुख कृषि, डेयरी उद्योग को अमेरिकी हितों के लिए तबाह करने पर सरकार आमादा है। इसे संसद के पटल पर रखने की न्यूनतम संवैधानिक मांग को मानने के लिए सरकार तैयार नहीं है। बयान में कहा गया कि देशी–विदेशी पूंजी के हितों को पूरा करने के लिए श्रम कानूनों को खत्म

करने का जो प्रयास मोदी सरकार कर रही है वह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। सच्चाई यह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद विदेशी पूंजी का प्रवाह भारत की तरफ बढ़ने के बजाय देश से बड़े पैमाने पर पूंजी पलायन कर रही है। श्रम कानूनों को बदलकर लाए लेबर कोड आधुनिक गुलामी के दस्तावेज हैं। इससे मजदूरों की छटंनी, असुरक्षित कार्यस्थियां, अमानवीय शोषण और बेहद कम मजदूरी पर काम करना बढ़ेगा। मजदूरों की इन हालातों के कारण क्रय शक्ति में आई कमी देश में पहले से जारी आर्थिक संकट व मंदी को और भी बढ़ाएगा। कार्यक्रमों में लखनऊ में एआईपीएफ प्रदेश महासचिव दिनकर कपूर, झारखंड में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय सिंह, पुष्पा उरांव, प्रयागराज में राजेश सचान, सीतापुर में प्रदेश सचिव डाक्टर बृज बिहारी, सुनीला रावत, सोनभद्र में राजेन्द्र प्रसाद गोंड, मंगरू प्रसाद श्याम, चंदौली में अजय राय, रहीमुद्दीन, आगरा में इंजीनियर दुर्गा प्रसाद आदि लोगों ने नेतृत्व किया।

जिस तरह सपा सरकार ने अनिल अंबानी के लिए गोलियां चलवाई, किसान उसे कभी भूल नहीं सकता : शाही

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जिस तरह आपने (सपा सरकार ने) अनिल अंबानी के लिए नोएडा और गाजियाबाद में गोलियां चलवाई, राज्य का किसान कभी उसे भूल नहीं सकता। विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल में सपा सदस्य अनिल प्रधान के किसानों के जमीन अधिग्रहण संबंधी पूरक प्रश्नों के उत्तर में सूर्य प्रताप शाही ने यह जवाब दिया। उन्होंने सदस्य को लक्ष्य करते हुए कहा, कहां की बात और कहां पूछ रहे हैं, चकबंदी विभाग की बात आप कृषि विभाग से पूछ रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि चित्रकूट से इलाहाबाद तक सड़क बनाइए, तो आप सोचते हैं कि आसमान में वह बन जाएगी।श्श शाही ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों से बातचीत कर बाजार दर के हिसाब से उनको मुआवजा दे रही है। उन्होंने तंज कसा, आपकी (सपा की सरकार) सरकार नहीं है कि जिस तरह आपने अनिल अंबानी के लिए नोएडा और गाजियाबाद गोलियां चलवाई, उसे कभी उत्तर प्रदेश का किसान भूल नहीं सकता। शाही ने कहा कि संजय डालमिया के लिए दुर्ग सीमेंट पर

आपने जो गोलियां चलवाई, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ६ारती पुत्र की सरकार थी। उन्होंने कहा कि योगी जी की सरकार में कभी इस तरह कोई घटना नहीं हुई है। इसके पहले अनिल प्रधान ने मंत्री से लिखित प्रश्न किया था कि क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में किसानों के कृषि उपकरणों, खाद एवं डीजल के दामों में वृद्धि के कारण कृषि लागत मूल्य अधिक हो रहा है। सूर्य प्रताप शाही ने इससे इनकार करते हुए कहा कि कृषि उपकरणों एवं खाद पर अनुदान अनुमन्य है तथा उत्तर प्रदेश में अधिकांश राज्यों की तुलना में डीजल का प्रति लीटर मूल्य कम है। उन्होंने कहा कि कृषकों को कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा सब मिशन आन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन एवं प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन–सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यूश्योजनाएं संचालित है।

ब्राउन गर्ल कैफे पर छापा, सील किया, 8 हुक्के, 23 फ्लेवर पैकेट जब्त

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी के गोमतीनगर इलाके में देर रात पुलिस ने ब्राउन गर्ल कैफे पर छापा मारकर कई सामान जब्त करते हुए कैफे सील कर दिया। यहां हुक्का बार भी चल रहा था। कार्रवाई के दौरान 8 हुक्के, 23 फ्लेवर पैकेट, 12 पाइप, 15 चिलम समेत भारी मात्रा में हुक्का सामग्री बरामद की गई। पुलिस ने कैफे को सील कर संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसी कैफे में 1 दिन पहले सेक्स रैकेट चलता मिला था। पुलिस के मुताबिक, 11 फरवरी की रात करीब 11.27 बजे सब–इंस्पेक्टर अरविंद कुमार टीम के साथ दयाल चौराहे पर गश्त पर थे। इसी दौरान सूचना मिली कि विकासखंड स्थित ब्राउन गर्ल कैफे (5/439) में अवैध रूप से हुक्का संचालित किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कैफे के अपर ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन के पास 7 हुक्के और 1 बटरफ्लाई हुक्का सजे मिले। इसके अलावा 12 पाइप, 15 चिलम, 17 बंद फ्लेवर पैकेट और 6 खुले फ्लेवर

पैकेट बरामद किए गए। वहीं कोयले का डिब्बा, 2 हीटर, 1 चिमटा और 2 पैकेट फिल्टर पाइप भी मौके से मिले।

छापेमारी के समय कैफे में कोई संचालक या कर्मचारी मौजूद नहीं मिला। पुलिस ने सभी सामान को जब्त कर जब्ती प्रपत्र तैयार किया। जांच में सामने आया कि कैफे के गेट पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 60ग30 सेमी का अनिवार्य चेतावनी बोर्ड नहीं लगा था। ध्रूमपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसका मानक बोर्ड नहीं लगा था। पुलिस ने कैफे को दो तालों बंद कर सील कर दिया। ब्राउन गर्ल कैफे करीब 1 साल से चल रहा था। देर रात तक कैफे में लड़का लड़कियां बैठकर हुक्का पीते थे। कैफे में बैठने वाली एक लड़की कम उम्र की लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर बड़े सपने दिखाई थी। दूसरे शहर से आई लड़कियां उसके जाल में फंसकर महंगे महंगे शौक की अदिति हो जाती थी।

स्वामी प्रसाद बोले, सरकार दबाव में काम कर रही

यूसीजी कानून, छात्र आत्महत्याओं और बजट पर राष्ट्रपति को सौंपेंगे ज्ञापन

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूसीजी कानून, विश्वविद्यालयों में बढ़ते भेदभाव, छात्र आत्महत्याओं और सरकार के कथित दोहरे रवैये को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के नाम पर कानून लाया गया, लेकिन उसके समर्थन में आवाज उठाने वालों के साथ ही सख्ती बरती जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में यूसीजी कानून लागू किया, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों में एससी, ओबीसी और अन्य वंचित वर्गों के साथ हो रहे भेदभाव को रोकना है। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि जब सवर्ण समाज के कुछ लोगों ने इस कानून के विरोध में प्रदर्शन किया तो सरकार का रवैया नरम रहा,

जबकि कानून के समर्थन में सड़क पर उतरे एससी–ओबीसी समाज के लोगों के साथ पुलिस ने बर्बरता पूर्ण व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में विधायक डॉ. पल्लवी पटेल के नेतृत्व में हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर जिस तरह पुलिस ने बल प्रयोग किया, वह निंदनीय है और लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है। मौर्य ने इसे सरकार का दोहरा मापदंड बताते हुए कहा कि इससे स्पष्ट है कि सरकार दबाव में काम कर रही है। राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आईआईटी कानपुर सहित कई केंद्रीय संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। एनसीआरबी के अनुसार एक वर्ष में 13,892 छात्र–छात्राओं ने आत्महत्या की, यानी प्रतिवर्ष लगभग 13 हजार से अधिक छात्र अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और विश्वविद्यालयों में व्याप्त भेदभाव तथा मानसिक प्रताड़ना इसका बड़ा कारण है। मौर्य ने घोषणा की कि वे कल महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपेंगे। इसमें मांग की जाएगी कि एससी और ओबीसी छात्रों के साथ हो रहे भेदभाव पर तत्काल रोक लगाई जाए, यूसीजी कानून को प्रभावी रूप से लागू किया जाए और आंदोलनरत छात्रों के साथ हुए दुर्व्यवहार की न्यायिक जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले अधिकांश छात्र इस कानून के पक्ष में हैं, लेकिन कुछ विकृत मानसिकता के लोग इसका विरोध कर माहौल बिगाड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बजट को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीबों और वंचितों के हित में नहीं है। यदि पिछले बजट का लगभग 50 प्रतिशत खर्च ही नहीं हुआ तो नया बजट लाने का क्या औचित्य है। पहले पुराने बजट का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए, तभी जनता का वास्तविक भला हो सकेगा। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान, जिसमें बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर टिप्पणी की गई थी, पर पूछे गए सवाल के जवाब में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री अक्सर इस प्रकार के बयान देते रहते हैं और इस पर वे विशेष रूप से कुछ नहीं कहना चाहते।

बजट में हुयी वादाखिलाफी पर कुलियों ने किया जोरदार प्रदर्शन

संवाददाता

लखनऊ। देश भर के कुली/यात्री सहायक संवर्ग की आजीविका व समाजिक सुरक्षा की अपनी पुरानी मांगों को लेकर राष्ट्रीय कुली मोर्चा ने चारबाग रेलवे स्टेशन पर जोरदार प्रदर्शन किया। जिसमें मुख्य रूप से रेल मंत्रालय द्वारा कुलियों की आजीविका व सामाजिक सुरक्षा की सर्वे रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत कर रिपोर्ट को सार्वजनिक करना है। साथ ही बजट में अपने खिलाफ हुयी बादाखिलाफी पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है।

46 लाख रुपए का हाउस टैक्स बकाया, नगर निगम ने सरोज इंस्टीट्यूट को सील किया

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ नगर निगम ने गुरुवार को सुल्तानपुर रोड पर सीलिंग की कार्रवाई की है। सरोज इंस्टीट्यूट की तरफ से नगर निगम का बकाया 46 लाख रुपए जमा नहीं करने पर यह एक्शन हुआ है। नगर निगम के कर अधीक्षक बनारसी दास ने बताया कि लंबे समय से टैक्स जमा करने के लिए इंस्टीट्यूट के साथ में बैठक की गई। नोटिस दिया गया, लेकिन नगर निगम का बकाया टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है। इसके चलते अब सीलिंग की कार्रवाई की गई है। मौके पर प्रशासनिक ब्लॉक के साथ में मेनगेट को सील किया गया है। इंस्टीट्यूट में टेक्निकल एजुकेशन

क्षेत्र से जुड़े छात्र पढ़ते हैं। नगर निगम की टीम सुबह के समय में कार्रवाई करने पहुंची तो इंस्टीट्यूट से जुड़े लोगों से उनकी जमकर तकरार हुई। कहा सुनी के बीच मौके पर नगर निगम की ईटीएफ फोर्स ने बीच बचाव किया। इंस्टीट्यूट से जुड़े लोगों ने कहा कि आप इस तरह से परिसर में नहीं आ सकते हैं। इसपर नगर निगम की टीम ने नगर निगम अधिनियम का हवाला देकर कार्रवाई करने की बाट कही। कर अधीक्षक बनारसी दास ने कहा कि हालात यह है कि कई बार मीटिंग करने और नोटिस देने के बाद भी कोई टैक्स नहीं जमा हो रहा है। मौके पर नगर निगम की तरफ से नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। यहां पर सीलिंग खोलने पर अधिनियम के अनुसार कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि टैक्स जमा नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। तय समय में टैक्स कलेक्शन कराने के लिए नगर निगम की टीम काम कर रही है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने कहा कि बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। लोगों से अपील है कि समय रहते हाउस टैक्स जमा कर दें, नहीं तो वित्त वर्ष खत्म होने के बाद पेनल्टी भी लगेगी।

केजीएमयू बाल रोग विभाग के प्रोफेसर पर छात्रा ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप, निलंबित

संवाददाता

लखनऊ। किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) में एक बार फिर छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जिसके बाद आरोपित एडिशनल प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है।

इस पूरे मामले की जांच विशाखा

कमेटी कर रही है। दरअसल, पूरा मामला 10 फरवरी का बताया जा रहा है, आरोपित एडिशन प्रोफेसर ने एमडी की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। जिसके बाद पीड़ित छात्रा ने इसकी शिकायत सीनियर अधिकारियों से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूत्र बताते हैं कि उसके बाद पीड़ित छात्रा के पिता ने केजीएमयू के कुलपति से मिलकर इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। तब जाकर आरोपित को निलंबित किया गया और अब केजीएमयू प्रशासन निष्पक्ष जांच की बात कह रहा है। केजीएमयू के प्रवक्ता प्रो. केके सिंह ने बताया है कि घटना की जानकारी होते ही एडिशनल प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है। जिससे जांच प्रभावित न हो। इसके अलावा विशाखा कमेटी की जांच रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जायेगी।

ओडीओपी योजना से बदली कारीगरों की तकदीर, 3.16 लाख लोगों को मिला रोजगार

ओडीओपी योजना से निर्यात दोगुना, पारंपरिक उत्पादों को मिला वैश्विक मंच, बजट में आवंटन बढ़ा
सरकार की ओर से अब तक 1,31,000 कारीगरों को नि:शुल्क प्रशिक्षण एवं टूल किट प्रदान की गई
कारीगरों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत पांच लाख रुपये तक की सुरक्षा भी दी जा रही

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू की गई 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ओडीओपी) योजना प्रदेश की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव का माध्यम बनकर उभरी है। वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई इस पहल ने पारंपरिक कारीगरों और स्थानीय उत्पादों को न केवल नई पहचान दी, बल्कि उन्हें बाजार, प्रशिक्षण और वित्तीय संबल भी उपलब्ध कराया। सरकार की ओर से अब तक 1,31,000 कारीगरों को नि:शुल्क प्रशिक्षण एवं टूल किट प्रदान की जा चुकी है। योजना के अंतर्गत कारीगरों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत पांच लाख रुपये तक की सुरक्षा भी दी जा रही है।

परंपरागत उत्पादों को मिला प्रोत्साहन

प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने बजट सत्र 2026–27 में प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू हुई इस योजना ने प्रदेश के पारंपरिक कारीगरों और उत्पादकों को नई पहचान दी है। यह योजना परंपरागत उत्पादों को प्रोत्साहन देने, कारीगरों को प्रशिक्षण, टूल किट और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर प्रभावी रूप से संचालित हो रही है। उन्होंने बताया कि सहारनपुर जनपद में 2275 कारीगरों को उन्नत टूल किट उपलब्ध कराई गई, जबकि 454 हस्तशिल्पियों को 16.26 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी वितरित की गई।

दोगुना से अधिक हुआ निर्यात

उन्होंने बताया कि आर्थिक दृष्टि से भी ओडीओपी योजना ने उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। वर्ष 2017–18 में प्रदेश का निर्यात 86 हजार करोड़ रुपये था, जो बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसमें लगभग 50 प्रतिशत योगदान ओडीओपी एवं हस्तशिल्प उत्पादों का बताया गया है। वर्ष 2018 से अब तक इस योजना के माध्यम से 3,16,000 लोगों को रोजगार सृजित हुआ है।

200 करोड़ के बजट का प्रावधान

वित्तीय प्रतिबद्धता भी इस योजना के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाती है। पिछले बजट में 145 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 135 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी वितरित की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में इसे बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया गया है। साथ ही प्रदेश के 79 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रांडिंग को मजबूती मिली है।

कारीगरों को स्वास्थ्य सुरक्षा और शिक्षा सुविधाओं से भी जोड़ा

उन्होंने कहा कि ओडीओपी केवल आर्थिक योजना नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक पुनर्जागरण का अभियान है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से कारीगरों को स्वास्थ्य सुरक्षा और शिक्षा सुविधाओं से भी जोड़ा गया है। इसके साथ ही 'वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन' जैसी नई पहल स्थानीय पहचान को और व्यापक मंच देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं।

आउटसोर्सिंग के खिलाफ बैंककर्मी लामबंद, हड़ताल पर रहे

बृजेश चतुर्वेदी

कन्नौज। बैंक कर्मी गुरुवार को हड़ताल पर रहे। कर्मियों ने बैंकों के बाहर एकत्र होकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। हड़ताल से जिले भर की बैंकों में 400 करोड़ का लेनदेन प्रभावित हुआ। यूपी बैंक इम्पलाइज यूनियन के आवाहन पर जिले भर की बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। बैंक में ताला डालकर उन लोगों ने प्रदर्शन किया। बैंक इम्प्लाइज यूनियन के जिला महामंत्री गौरव मिश्रा ने बताया कि बैंकों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों को रखने की तैयारियां चल रहीं हैं। इसके अलावा बैंकों के निजीकरण के भी प्रयास हो रहे हैं। बैंकों में पर्याप्त स्टाफ न होने से कर्मियों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा। लिहाजा बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती की जानी चाहिए, ताकि कर्मियों पर काम का बोझ कम हो। इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाली की भी प्रमुख मांग है। जिसको लेकर सभी बैंकों में हड़ताल रखी गई है। उत्तर प्रदेश बैंक इम्पलाईज़ यूनियन कन्नौज के प्रतिनिधि यूनिट के गौरव मिश्रा ने बताया कि हड़ताल से कन्नौज जिले की बैंकों में करीब 400 करोड़ का लेनदेन प्रभावित हुआ है। प्रदर्शन के दौरान जिला मंत्री गौरव द्विवेदी, उपाध्यक्ष सुमित द्विवेदी, जिला मंत्री सचिन चौहान, राजेन्द्र यादव, अमरजीत, मुकेश कुमार, नवीन, रामगोपाल समेत कई कर्मी मौजूद रहे।

सीएम योगी ने दिया ब्रह्मोस संग 'हार्ड पावर' विजन

मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बदली कवर इमेज
अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने वाली सरकार के मुखिया ने दिया 'नए यूपी' का संकेत

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने वाली सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 'नए यूपी' की बढ़ती ताकत का संकेत दिया। बजट 2026–27 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कवर इमेज बदल दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस संग अपनी फोटो लगाकर 'हार्ड पावर' विजन" का संदेश दिया। सोशल मीडिया हैंडल पर मुख्यमंत्री का यह संदेश बताता है कि लखनऊ में ब्रह्मोस निर्माण के जरिए उत्तर प्रदेश एक तरफ रक्षा उत्पादन का उभरता वैश्विक हब हो गया है। वहीं दूसरी ओर 9.12 लाख करोड़ का बजट और सामरिक शक्ति के संगम का भी संकेत प्रदेशवासियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। बजट के जरिए सीएम योगी ने संदेश दिया कि यूपी की अर्थव्यवस्था "फर्श से अर्श तक पहुंच गई है, जो यूपी के विकास, सुरक्षा और निवेश के त्रिवेणी मॉडल को प्रदर्शित करता है। योगी का यह "'सुपरसोनिक केसरिया' संदेश बताता है कि उत्तर प्रदेश विकास का इंजन और प्रदेशवासियों की सुरक्षा का कवच भी बन गया है।

संक्षिप्त

महान टेनिस प्लेयर फेडरर टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल, सम्मान समारोह के टिकट दो मिनट में बिके

एजेंसी

न्यूपोर्ट (अमेरिका)। रोजर फेडरर ने भले ही टेनिस को अलविदा कह दिया हो, लेकिन उनका जादू अब भी प्रशंसकों पर सर चढ़कर बोलता है जिसकी बानगी यहां उन्हें अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल करने के समारोह के टिकटों की भारी मांग में देखने में मिली। फेडरर से जुड़े इस समारोह के सभी टिकट दो मिनट में बिक गए। आयोजकों ने आउटडोर पार्टी के लिए अलग से अतिरिक्त टिकट जारी किए जो हाथों हाथ बिक गए। आखिर में आयोजकों को कहना पड़ा कि उनकी क्षमता सीमित है और वह अधिक टिकट जारी नहीं कर सकते हैं। आयोजक हॉल ऑफ फेम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, श्एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक स्थल होने के कारण हमारी क्षमता सीमित है। हॉल ने कहा कि उसे पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी फेडरर को लेकर कितना उत्साह होगा। इस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी को 29 अगस्त को प्रसारक मैरी कैरिलो के साथ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। न्यूपोर्ट स्थित इस प्रतिष्ठित हॉल में होने वाले मुख्य समारोह के लिए पहले से उपलब्ध 900 टिकटों के अलावा हॉल अपने 3,600 सीटों वाले स्टेडियम को एक विशेष कार्यक्रम के लिए खोलेगा। इसके बावजूद हॉल की प्रवक्ता मेगन एर्ब्स ने कहा कि 4,500 टिकट दो मिनट के भीतर ही बिक गए।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ शासन के मध्य उन्नत वेतन पैकेज के लिए हुआ एमओयू

व्यक्तिगत दुर्घटना पर 1.25 करोड़ रूपए का बीमा कवर
हवाई दुर्घटना बीमा एक करोड़ रूपए
बिटिया की शादी और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी लाभ

बीएनई

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के नियमित कर्मचारियों को आकर्षक एवं व्यापक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ शासन के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत बैंक में वेतन खाता संचालित करने वाले राज्य सरकार के सभी नियमित कर्मचारियों को 'गवर्नमेंट प्राइड सैलरी सेविंग स्कीम' के अंतर्गत उन्नत नि:शुल्क सुविधाएं एवं बीमा कवर प्रदान किए जाएंगे। समझौते के अनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा खाताधारक कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा एक करोड़ 25 लाख रूपए तक, हवाई दुर्घटना बीमा एक करोड़ रूपए तक, स्थायी पूर्ण विकलांगता कवर एक करोड़ 25 लाख रूपए तक तथा टर्म इंश्योरेंस 10 लाख रूपए प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही गोल्डन आवर के अंतर्गत 1 लाख रूपए तक कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध होगी। कर्मचारियों को बालिका विवाह लाभ 10 लाख रूपए तक एवं बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु 10 लाख रूपए तक का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त खाताधारकों को अन्य आकर्षक बैंकिंग लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे तथा स्वास्थ्य बीमा पर टॉप–अप जैसी वैकल्पिक सुविधाएं रियायती दरों पर प्रदान की जाएंगी। यह समझौता ज्ञापन 10 फरवरी 2026 को श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा, विशेष सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन तथा श्री वी. वेंकटेश, अंचल प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, रायपुर अंचल की उपस्थिति में संपन्न हुआ। यह पहल राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक एवं लाभप्रद बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्यार का इजहार पड़ा भारी! : ओलंपिक स्टार के ऑन-एयर कबूलनामे पर एक्स-गर्लफ्रेंड नाराज, धोखे पर दिया करारा जवाब

एजेंसी

मिलानो। नॉर्वे के बायएथलीट स्टुर्ला होम लेग्रेड ने मिलान–कोर्टिना विंटर ओलंपिक में पुरुषों की 20 किमी इंडिविजुअल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। खेल उपलब्धि सुर्खी बनती, उससे पहले लाइव इंटरव्यू में किया गया उनका निजी कबूलनामा खबरों पर छा गया। भावुक होते हुए उन्होंने अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड को धोखा देने की बात मानी और दुनिया के सामने प्यार जताकर उसे वापस पाने की कोशिश की। हालांकि, उनकी इस सार्वजनिक अपील का जवाब उतना नरम नहीं था। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने अब करारा जवाब दिया है। नॉर्वेइयन अखबार वीजी से बातचीत में उन्होंने साफ कहा, श्पूरी दुनिया के सामने प्यार का इजहार करने के बाद भी उसे माफ करना आसान नहीं है।

उन्होंने आगे कहा, श्मैंने खुद को इस स्थिति में रखने का चुनाव नहीं किया, और इसे झेलना तकलीफदेह है। हमारी बात हुई है और उसे मेरे जज्बात का पता है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती इंटरव्यू में लेग्रेड ने बताया कि वह छह महीने पहले उनसे मिले थे, लेकिन तीन महीने पहले उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। आंसुओं के बीच उन्होंने कहा, वह दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारी इंसान हैं और हर कोई जान ले कि वह मेरे लिए कितनी मायने रखती हैं। समय पर उठा सवाल आलोचकों का कहना है कि इस कबूलनामे ने उसी इवेंट में जोहान–ओलाव बोटन के स्वर्ण पदक की चमक फीकी कर दी। बोटन ने अपनी जीत दिसंबर में दिवंगत हुए सिवर्ट गुट्टॉर्म बक्केन को समर्पित की थी, लेकिन चर्चा का केंद्र लेग्रेड का बयान बन गया।

EU के देशों समेत US-UK के साथ व्यापार समझौतों से भारत को कितना लाभ, निर्यातक क्या बोले?

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों (EPCs) और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने हाल में संपन्न हुए व्यापार समझौतों से उत्पन्न अवसरों पर विस्तृत चर्चा की। पिछले छह वर्षों में प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ कई एफटीए हुए मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें विभिन्न ईपीसीएस और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधियों ने पिछले छह वर्षों में प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ कई मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया। चर्चा का मुख्य फोकस कहां पर रहा? बैठक का मुख्य फोकस इन समझौतों से मिलने वाले लाभों को अधिकतम करने की रणनीति पर रहा। चर्चा में निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, नए बाजारों तक पहुंच का विस्तार करने और वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने पर जोर दिया गया। मंत्री ने कहा कि इन समझौतों ने उद्योग, सेवा क्षेत्र और निर्यातकों के लिए व्यापक अवसर खोले हैं। गोयल ने यह भी रेखांकित किया कि उद्योग संगठनों और ईपीसीएस की भूमिका महत्वपूर्ण है, ताकि भारतीय व्यवसाय इन समझौतों के लाभों का पूर्ण उपयोग कर सकें। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग को सहयोग देने, निर्यात बढ़ाने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। 2025 में तेज हुई व्यापार कूटनीति साल 2025 में भारत ने कई अहम व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर कर अपनी व्यापार कूटनीति को नई गति दी। 24 जुलाई को भारत–ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA) पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे वस्त्र और रत्न–आभूषण जैसे क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। 18 दिसंबर को भारत–ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) पर हस्ताक्षर हुए। 22 दिसंबर को भारत–न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता को औपचारिक रूप से संपन्न किया गया। इसके अलावा, 1 अक्तूबर 2025 से भारत–ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टाइन के साथ) प्रभावी हुआ, जिसके तहत 100 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता सामने आई। 2026 में बड़ी प्रगति 27 जनवरी 2026 को भारत ने भारत–ईयू मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर कर यूरोपीय संघ के विशाल और समृद्ध बाजार तक भारतीय कारोबारियों को प्राथमिकता आधारित पहुंच दिलाई। इसके तुरंत बाद 7 फरवरी को भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की घोषणा हुई, जिसके तहत अमेरिकी टैरिफ दरें 50 प्रतिशत के उच्च स्तर से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गईं।

आईपीओ में नया रिकॉर्ड संभव, चुनौतियों के बीच कंपनियां जुटा सकती हैं 2.50 लाख करोड़

एजेंसी

नई दिल्ली। वैश्विक अनिश्चितता, देशों के बीच व्यापार समझौतों को लेकर हो रही देरी और भू–राजनीतिक तनाव के बीच भारतीय बाजार में कंपनियां इस साल आईपीओ से रिकॉर्ड रकम जुटा सकती हैं। विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनियां 2026 में निर्गम से 2.50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाएंगी, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 1. 75 लाख करोड़ था। अनिश्चतताओं के बावजूद इस साल जनवरी से अब तक पांच कंपनियों ने आईपीओ से 8,806 करोड़ रुपये जुटाए हैं। पिछले साल की समान अवधि में 7 कंपनियों ने 6,113 करोड़ रुपये जुटाए थे। इस साल अब तक बड़े निर्गम में फ्रैक्टल ने 2,833 करोड़, शैडोफाक्स ने 1,907 करोड़, अमागी मीडिया ने 1,788 करोड़ और भारत कोकिंग ने 1,068 करोड़ जुटाए हैं। विश्लेषकों के मुताबिक, 2025 में स्टार्टअप आईपीओ के रिकॉर्ड प्रदर्शन के बाद 2026 में नई पीढ़ी की तकनीकी कंपनियों के सार्वजनिक लिस्टिंग की ओर बढ़ने की गति और भी मजबूत दिखाई दे रही है। 20 स्टार्टअप पहले ही भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के समक्ष मसौदा

दाखिल कर चुके हैं, जबकि 24 अन्य स्टार्टअप अपने आईपीओ योजनाओं को अंतिम रूप देने के विभिन्न चरणों में हैं। हालांकि, 2026 में स्थिति में बदलाव आने की संभावना है, क्योंकि सार्वजनिक बाजार के निवेशक नई पीढ़ी की तकनीकी कंपनियों में निवेश करते समय मजबूत बुनियादी बातों, लाभप्रदता और कम नकदी खपत को प्राथमिकता देंगे। 50,000 करोड़ जुटाएंगी नई पीढ़ी की कंपनियां 2026 में सूचीबद्ध होने की योजना बना रही नई पीढ़ी की कंपनियों की सूची पिछले साल की तरह ही भीड़भाड़ वाली होगी। ये कंपनियां करीब 50,000 करोड़ जुटा सकती हैं। इनमें फोनपे 13,500 करोड़, जेप्टो 12,000 करोड़, ओयो 6,650 करोड़, शिपरॉकेट 2,342 करोड़ और बोट 1,500 करोड़ जुटाएंगी। स्टार्टअप कंपनियों ने पिछले साल 35,600 करोड़ रुपये थे। इनमें प्रमुख रूप से लेंसकार्ट 7,278 करोड़, ग्रो 6,632 करोड़ रुपये, मीशो 5,421 करोड़, पाइन लैब 3,900 करोड़ और फिजिक्सवाला ने 3,820 करोड़ रुपये जुटाए थे। लिस्टिंग के बाद अच्छा प्रदर्शन वेंचर निवेशकों और बैंकरों ने चेतावनी दी है कि पिछले साल की गति को बनाए रखना बाजार स्थितियों के साथ–साथ घाटे में चल रहे या हाल ही में लाभ कमाने वाले तकनीकी व्यवसायों के प्रति निवेशकों की रुचि पर निर्भर करेगा। विश्लेषकों के मुताबिक, 2025 में नई पीढ़ी की कंपनियों का लिस्टिंग के बाद प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, जो सार्वजनिक बाजार के निवेशकों के लिए ठोस रिटर्न का संकेत देता है। ऐसे में यह क्षेत्र अधिक परिपक्व माना जा रहा है। बड़े निवेशकों की पकड़ बड़े घरेलू और विदेशी संस्थान आईपीओ पोर्टफोलियो में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं।

बिग बॉस 14 फेम निक्की तंबोली के नाम पर धोखाधड़ी, फैंस और करीबी लोगों को किया अलर्ट; कहा- यह एक स्कैम...

एजेंसी

निक्की तंबोली ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करते हुए फैंस, करीबी लोगों और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को सचेत किया है। उन्होंने बताया है कि कोई उनके नाम पर स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। इस व्यक्ति के बारे में निक्की ने जानकारी भी सोशल मीडिया पर साझा की है। जानिए, निक्की ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा? निक्की तंबोली ने फेक नंबर का जिक्र किया निक्की तंबोली ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करते हुए एक नंबर और चौट शेयर की। जिसमें एक अनजान नंबर से उनके करीबी लोगों से कॉन्टैक्ट किया जा रहा है। इस पोस्ट के साथ निक्की लिखती हैं, 'कोई मेरा नाम और तस्वीर इस्तेमाल करके फेक नंबर से लोगों को मैसेज कर रहा है। यह मैं नहीं हूं। प्लीज इस शख्स को अहमियत ना दें।

रिप्लाई ना करें। यह स्कैम हो सकता है। कृपया इस नंबर को रिपोर्ट करें, ब्लॉक करें।' द 50 रियलिटी शो में नजर आईं निक्की तंबोली हाल ही में शुरू हुए रियलिटी शो 'द 50' में निक्की तंबोली और उनके बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल भी नजर आए। यह दोनों काफी समय से डेट कर रहे हैं। अरबाज पटेल को आखिरी बार शो राइज एंड फॉल में देखा गया था। वहीं निक्की को शो 'सेलिब्रिटी मास्टर शेफ' में देखा गया था। इससे पहले वह बिग बॉस 14 का हिस्सा रह चुकी हैं।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743